एन.के. सोढ़ी, न्यायाधीश के सामने

संजय कुमार गुप्ता,-याचिकाकर्ता,

विरूद्ध

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र,

-प्रतिवादी

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 859

23 अप्रैल, 1991.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226—उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के नियम—नियम 19.3 और 19.4—अप्रैल, 1988 में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार—23 जुलाई, 1988 को एक पेपर में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कियां—1 जून, 1988 को पुनर्मूल्यांकन के तरीके को निर्धारित करने वाले नियमों में संशोधन किया गया—असंशोधित नियमों के तहत याचिकाकर्ता मूल अंकों के विपरीत अंक 45 अंको का हकदार है - संशोधित नियमों के तहत उम्मीदवार का परिणाम अपरिवर्तित रहता है - जिस समय उम्मीदवार ने परीक्षा दी थी उस समय के नियमों के तहत उम्मीदवार को 45 अंक दिए जाएंगे।

माना गया कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के गणित पेपर- II का पुनर्मूल्यांकन करते समय असंशोधित नियमों को लागू करना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 1988 में परीक्षा दी, जबकि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियम जून, 1988 के बाद में बदल दिए गए और इस प्रकार, उन्हें संशोधित नियमों की कोई सूचना नहीं मिल सकी।

(पैरा 5 एवं 6)

आगे कहा गया, कि एक स्वायत्त निकाय होने के नाते विश्वविद्यालय को किसी भी परीक्षा के लिए अर्हता अंक और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियमों सहित परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अपेक्षित नियमों को बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह परीक्षाओं से पहले ही किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब कोई उम्मीदवार किसी परीक्षा में उपस्थित होता है, तो वह केवल उन नियमों द्वारा शासित होगा जो उस समय लागू हैं, न कि किसी बाद में संशोधित नियम से और मेरी राय में, यह सिद्धांत पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले नियमों पर भी समान रूप से लागू होगा। यह एक सामान्य ज्ञान का विषय है कि परिणाम घोषित होने के बाद, एक विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों के नियम और विनियमन कभी-कभी पेपर के पुनः मूल्यांकन के लिए प्रावधान करते हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों को परिणाम की घोषणा की तारीख से निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना होता है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में भी, परीक्षा के समय प्रभावी नियम उक्त परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को नियंत्रित करेंगे।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

i. नियम 19.4 के साथ प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों (अनुलग्नक पी-2) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए;

ii. कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, भी जारी किया जा सकता है;

iii. प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस जारी करने से मुक्ति दी जाएगी;

iv. अनुलग्नक पी-1 और पी-2 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की अनुमति दी जाए;

v. रिट याचिका को लागत सहित स्वीकार किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री अनिल खेत्रपाल, वकील।

प्रतिवादी की ओर से श्री सुभाष आहूजा, वकील।

निर्णय

एन.के. सोढ़ी, न्यायाधीश.

(1) याचिकाकर्ता संजय कुमार गुप्ता ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई बी.एस.सी. अंतिम (इलेक्ट्रॉनिक्स) परीक्षा अप्रैल, 1988 में दी और कुल 450 में से 240 अंक प्राप्त किए। गणित के पेपर- II में, उन्होंने 75 में से 33 अंक प्राप्त किए, जो उन्हें मूल मूल्यांकनकर्ता जिन्हें उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए भेज दी गई थी उन परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए थे। इन अंकों से संतुष्ट नहीं होने पर, याचिकाकर्ता ने 23 जुलाई, 1988 को अपने गणित पेपर- II के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के नियमों (इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) के खंड 19.4 के अनुसार किया जाना चाहिए। इस खंड के अनुसार, किसी उम्मीदवार के परिणाम को नियमों के खंड 19.3 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन स्कोर के आधार पर संशोधित किया जा सकता है, यदि परिणाम का चरित्र बदल दिया गया हो। परिणाम की प्रकृति का अर्थ है 'कम्पार्टमेंट में फेल', 'पास होने में फेल', 'कम्पार्टमेंट में पास' या 'इसके विपरीत' 'डिवीजन में बदलाव' या जहां पुनर्मूल्यांकन पर स्कोर 5 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ता या घटता है,

संबंधित पेपर के लिए सौंपे गये। अप्रैल, 1988 में, जब याचिकाकर्ता ने परीक्षा दी थी, तब नियमों का खंड 19.3 इस प्रकार था:

"19.3 पुनर्मूल्यांकन दो स्वतंत्र परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के बाद अंतिम परिणाम मूल परीक्षक के पुरस्कार सहित तीन पुरस्कारों में से दो उच्च पुरस्कारों का औसत होगा जिसमे मूल मूल्यांकनकर्ता के पुरस्कार शामिल होगा। आंशिक चिह्न, यदि कोई हो, को पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा।"

इस नियम के अनुसार, एक उम्मीदवार के पेपर का दो स्वतंत्र परीक्षकों द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाना था और पुनर्मूल्यांकन के बाद अंतिम परिणाम मूल परीक्षक के पुरस्कार सहित तीन पुरस्कारों में से दो उच्च पुरस्कारों का औसत होना था जिसमे मूल मूल्यांकनकर्ता के पुरस्कार शामिल होगा। इस नियम को 1 जून, 1988 से संशोधित किया गया था और संशोधित नियम 19.3, जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"19.3 यदि मूल परीक्षक और पुनर्मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए पुरस्कारों का औसत मूल स्कोर से पेपर के अधिकतम अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो औसत स्कोर को पेपर में पुनर्मूल्यांकन स्कोर के रूप में लिया जाएगा। , पुनर्मूल्यांकन के नियमों के खंड 19.4 के अधीन, यदि, तथापि, पुनर्मूल्यांकन स्कोर मूल स्कोर को अधिकतम अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने/घटाने के लिए होता है, तो मामला दूसरे पुनर्मूल्यांकनकर्ता और तीन पुरस्कारों के पास भेजा जाएगा। मूल परीक्षक और दो पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए पुरस्कार, दो करीबी पुरस्कारों के औसत को मूल्यांकन किए गए पुनर्मूल्यांकन

स्कोर के रूप में लिया जाएगा। बशर्ते कि यदि कोई पुरस्कार' अन्य दो के समान रूप से करीब है, अर्थात 54, 56, 58 पर परिणाम दो उच्च पुरस्कारों के औसत पर घोषित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि तीन में से दो परीक्षक (दो पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं सहित) किसी उम्मीदवार को कम से कम उत्तीर्ण अंक देते हैं और दो करीबी पुरस्कारों का औसत उसके स्कोर को न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कम कर देता है, तो उम्मीदवार को उस पेपर में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दिए जाएंगे :-

बशर्ते कि यदि कोई छात्र पुनर्मूल्यांकन के बाद सीमांत अंकों, जैसे कि एक या दो अंकों से असफल हो जाता है, तो या तो दो पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं या एक पुनर्मूल्यांकनकर्ता, जैसा भी मामला हो, के औसत अंकों को ध्यान में रखा जाएगा और छात्र को एक या दो का ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण होने दिया जाए।

आंशिक चिह्न, यदि कोई हो, को पूर्ण चिह्न तक पूर्णांकित किया जाएगा। यदि संशोधित परिणाम अभ्यर्थी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो भी उसे इसे स्वीकार करना होगा।"

संशोधित नियम संबंधित पेपर में पुनर्मूल्यांकित अंक निर्धारित करने के तरीके को बदल देता है। इस संशोधन के अनुसार, यदि मूल परीक्षक और पुनर्मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए पुरस्कारों का औसत मूल अंक से संबंधित पेपर के अधिकतम अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो औसत अंक को पुनः प्राप्तांक के रूप में लिया जाएगा -उस पेपर में मूल्यांकन स्कोर नियमों के खंड 19.4 के अधीन है। यदि, हालांकि, पुनर्मूल्यांकन स्कोर मूल स्कोर को अधिकतम अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने या घटाने के लिए होता है, तो मामला दूसरे

मूल्यांकनकर्ता को भेजा जाना चाहिए और तीन पुरस्कारों में से दिए गए पुरस्कारों को भेजना होगा। मूल परीक्षक और दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा, दो निकटतम पुरस्कारों के औसत को पुनर्मूल्यांकन स्कोर के रूप में लिया जाएगा, बशर्ते कि यदि एक पुरस्कार अन्य दो के समान रूप से करीब है, तो परिणाम दो के औसत पर उच्च पुरस्कार घोषित किया जाएगा।

(2) याचिकाकर्ता ने 23 जुलाई, 1988 को अपने गणित पेपर-2 के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने ऊपर उद्धृत संशोधित नियम के अनुसार पाया कि उसके पुनर्मूल्यांकन स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ था और वह सहायक रजिस्ट्रार (पुनर्मूल्यांकन) द्वारा इस आशय का एक संचार (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-1) भेजा गया। चूँकि जब याचिकाकर्ता ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया तब तक संशोधित नियम लागू हो चुका था, विश्वविद्यालय ने संशोधन के आलोक में उसकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया, विश्वविद्यालय की इस कार्रवाई को याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में चुनौती दी है।

(3) रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश किया गया एकमात्र तर्क यह है कि चूंकि उसने अप्रैल, 1988 में अपनी परीक्षा दी थी, उस समय लागू पुनर्मूल्यांकन सहित सभी नियम उस समय पर थे वही लागू होंगे और संधोधित नियम केवल उन छात्रों पर लागू होगा जो संशोधन लागू होने के बाद आयोजित परीक्षाओं में शामिल होंगे। रिट याचिकाकर्ता का रुख विश्वविद्यालय द्वारा विरोधाभासी है जो इस आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराना चाहता है कि जब याचिकाकर्ता ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, तो संशोधित नियम पहले ही लागू हो चुका था।

(4) पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों पर गहन विचार करने के बाद। मुझे रिट याचिकाकर्ता के तर्क में दम नजर आता है। यह सच है कि एक स्वायत्त निकाय होने के नाते विश्वविद्यालय को किसी भी परीक्षा के लिए अर्हता अंक और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियमों सहित परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अपेक्षित नियमों को बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह परीक्षाओं से पहले ही किया जाना चाहिए। जिसे लागू करने की मांग की जा रही है और इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। जब कोई उम्मीदवार किसी परीक्षा में उपस्थित होता है, तो वह केवल उन नियमों द्वारा शासित होगा जो उस समय लागू हैं, न कि किसी बाद में संशोधित नियम द्वारा। मेरी राय में, यह सिद्धांत पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले नियमों पर भी समान रूप से लागू होगा। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि परिणाम घोषित होने के बाद, विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों के नियम और विनियम कभी-कभी एक पेपर के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान करते हैं जिसके लिए उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने की तारीख से एक निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करना होता है और इसलिए पुनर्मूल्यांकन के मामले में भी, परीक्षा के समय लागू नियम उन उम्मीदवारों को नियंत्रित करेंगे जो उक्त परीक्षा में बैठे थे। मैंने जो विचार रखा है, उसमें मुझे 1967 की एल.पी.ए. क्रमांक 97 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले से समर्थन मिलता जिसका निर्णय 17 जुलाई 1968 को हुआ जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:-

> "विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है और परीक्षाओं के संचालन और डिग्री के लिए आवश्यक अर्हता अंकों से संबंधित अपेक्षित नियमों को बदलने के मामले में उसे पूरा अधिकार है, बशर्ते कि नियम उस परीक्षा से काफी पहले बनाए जाएं जो एक उम्मीदवार को देनी होती है।"

(जोर दिया गया)

डिवीजन बेंच का यह विचार कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवार को नियमों में किसी भी बदलाव की पर्याप्त अग्रिम सूचना होनी चाहिए, जिससे उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, पंजाब विश्वविद्यालय विरूद्ध सुभाष चंदर में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा अनुमोदित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले में, रिट याचिकाकर्ता सुभाष चंदर एम.बी.बी.एस. में शामिल हुए। पाठ्यक्रम 1965 में जब नियम 7.1 एम.बी.बी.एस. से संबंधित था, परीक्षा में यह प्रावधान था कि एक उम्मीदवार जो एक या एक से अधिक प्रश्नपत्रों/विषय और/या कुल अंकों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे परीक्षा उत्तीर्ण घोषित करने के लिए उसके सर्वोत्तम लाभ के लिए कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंक दिए जा सकते हैं। इस नियम को मई, 1970 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत एम.बी.बी.एस. के मामले में अनुग्रह अंक दिए जा सकते थे, परीक्षा में प्रत्येक विषय के कुल योग का 1 प्रतिशत तक दिया जा सकता था, न कि सभी विषयों के कुल योग का 1 प्रतिशत, जैसा कि पहले नियम था। इसका संशोधन रिट याचिकाकर्ता अंततः अंतिम एमज.बी.बी.एस. के लिए उपस्थित हुआ। वर्ष 1974 में 9 साल बाद परीक्षा दी और सैद्धांतिक परीक्षा में 200 में से 95 अंक प्राप्त किए, जब उत्तीर्ण अंक 100 थे। उस पेपर के कुल अंक 400 थे और जिन चार विषयों में वह उपस्थित हुए थे, उनके कुल अंक 1600 थे। सुभाष चंदर के इस तर्क को खारिज करते हुए कि वह पुराने नियम के आधार पर 16 अनुग्रह अंकों के हकदार थे, जो 1965 में उस समय लागू था जब वह एम.बी.बी.एस. में शामिल हुए थे। पाठ्यक्रम, उनके आधिपत्य को निम्नानुसार देखा गया:-

"जब प्रतिवादी 1, सुभाष चंदर को एम.बी.बी.एस. में भर्ती कराया गया था,1965 में पाठ्यक्रम, नियम 7.1 जैसा कि तब था और ऊपर निकाला गया है, बशर्ते कि

जो उम्मीदवार एक, या अधिक पेपर/विषयों/या कुल में असफल हो जाता है, उसे व्यावहारिक और आंतरिक को छोड़कर कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंक दिए जा सकते हैं। उसके सर्वोत्तम लाभ के लिए मूल्यांकन किया जाए ताकि उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जा सके। सुभाष चंदर, प्रतिवादी 1, जो अंतिम एम.बी.बी.एस. के लिए उपस्थित हुए, केवल नौ साल बाद 1974 में परीक्षा में चार विषयों अर्थात् मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र और ईएनटी और मिडवाइफरी में उत्तीर्ण होना था, जिनमें से प्रत्येक के लिए कुल 400 अंक थे। उन्होंने मेडिसिन, सर्जरी और आई और ईएनटी में 202, 225 और 204 अंक हासिल किए और उन्हें उन विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने की घोषणा की गई, मिडवाइफरी में दो भाग शामिल थे, सिद्धांत और व्यावहारिक, जिनमें से प्रत्येक के लिए कुल 200 अंक थे। सुभाष चंदर प्रतिवादी 1 ने व्यावहारिक परीक्षा में 200 में से 106 अंक प्राप्त किए और सैद्धांतिक परीक्षा में 200 में से केवल 95 अंक प्राप्त किए। चूंकि 1974 में उन्होंने जिन चार विषयों की परीक्षा दी थी, उनका कुल योग 1600 अंक था, पुराने नियमन 25 के तहत नियम 7.1 के साथ पढ़ा गया, क्योंकि यह 1965 में पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश के समय था, वह 16 ग्रेस के हकदार होंगे। अंक और परीक्षा उत्तीर्ण घोषित कर दी गई होगी क्योंकि मिडवाइफरी में (सैद्धांतिक) परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त वास्तव में 95 अंकों में 16 अनुग्रह अंक जोड़ने से आवश्यक न्यूनतम 50 प्रतिशत पूरा हो जाएगा। लेकिन बहुत पहले ही सुभाष चंदर ने एम.बी.बी.एस. की अंतिम परीक्षा दी। 1974 की परीक्षा में एम.बी.बी.एस. को अनुग्रह अंक देने से संबंधित नियम और बी.डी.एस. जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियम 2.1 में एक अपवाद जोड़कर

1970 में विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा छात्रों की संख्या बदल दी गई थी। यह तर्क नहीं दिया गया कि यह परिवर्तन करने के लिए सरकार की मंजूरी नहीं ली गई थी। अपवाद कहता है कि एम.बी.बी.एस. के मामले में और बी.डी.एस. हालाँकि परीक्षाओं में अनुग्रह अंक प्रत्येक विषय के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक दिए जाएंगे, न कि सभी विषयों के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक; दूसरे शब्दों में, इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक विषय एक अलग इकाई होगी और जो अभ्यर्थी किसी विषय में 1 प्रतिशत से अधिक अनुत्तीर्ण होता है, उसे उस विषय में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक दिए जा सकते हैं। 1970 में संशोधित इस नियम के तहत, प्रतिवादी 1, सुभाष चंदर, केवल मिडवाइफरी के लिए 400 अंकों के कुल 1 प्रतिशत के ग्रेस मार्क्स के रूप में केवल 4 अंकों के हकदार थे। चूंकि मिडवाइफरी में (सिद्धांत) परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए 95 अंकों में 4 अनुग्रह अंक जोड़ने पर, जिसके लिए कुल 400 अंकों में से 200 अंक थे, उस विषय के लिए कुल 400 अंकों में से केवल 99 अंक बनते हैं, यह 50 से कम था। प्रति व्यक्ति और उसे मिडवाइफरी में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया और उस विषय की परीक्षा फिर से देने के लिए कहा गया।

*** *** ***

*** *** ***

यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि 1974 में अंतिम परीक्षा में बैठने वाले सुभाष चंदर को अनुग्रह अंक देने से संबंधित नियम में 1970 में किए गए बदलाव के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी या वह इस बदलाव से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे।"

(5) वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 1988 में परीक्षा दी, जबकि पुनर्मूल्यांकन के संबंध में नियम बाद में जून, 1988 में बदल दिए गए और इस प्रकार, उसे संभवतः संशोधित नियमों की कोई सूचना नहीं मिल सकी।

(6) निष्कर्ष के तौर पर, मेरा मानना है कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के गणित पेपर-2 का पुनर्मूल्यांकन करते समय गैर-संशोधित नियम लागू करना चाहिए था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मूल परीक्षक ने 75 में से 33 अंक दिए थे जबकि पुनर्मूल्यांकन पर दूसरे परीक्षक ने 75 में से 51 अंक दिए थे और तीसरे परीक्षक ने केवल 75 में से 38 अंक दिए थे। असंशोधित नियम को लागू करते हुए, पुनर्मूल्यांकन के बाद अंतिम परिणाम मूल परीक्षक के पुरस्कार सहित तीन पुरस्कारों में से दो उच्च पुरस्कारों का औसत होना चाहिए। दो उच्च पुरस्कारों का औसत 44.5 आता है और चूँकि अंश को पूर्ण अंक तक पूर्णांकित किया जाना है, याचिकाकर्ता को 75 में से 45 अंक प्राप्त करने के लिए माना जाना चाहिए और विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाता है, रिट याचिका बिना किसी लागत के स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा